

## उत्तर प्रदेश सरकार का त्वरति न्याय की दशा में प्रयास

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह वभाग ने पछिले वर्षों में हुई कार्रवाई को आधार बनाते हुए प्रभावी पैरवी की कार्ययोजना तैयार की है।

### प्रमुख बढि

- छह माह की इस कार्ययोजना में मृत्युदंड की सज़ा वाले अपराधों में अभयिक्तों और उम्रकैद की सज़ा वाले 300 अभयिक्तों को जेल भजिवाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के तहत तेज़ी से पैरवी कर 10 प्रकरणों में आरोपति को 1 माह के भीतर सज़ा दलाई जाएगी।
- इसी प्रकार गृह वभाग द्वारा एक-दो वर्षीय कार्ययोजना का भी नरिमाण कथिा गया है।
- गौरतलब है का उत्तर प्रदेश का 2019 में महिलाओं के प्रत अपराधों में सज़ा दलाने का प्रतशित 55.2 था, जो 2020 में बढकर 61 हो गया।
- महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से ही प्रदेश में मशिन शकत की शुरुआत की गई थी। साथ ही उत्तर प्रदेश डजिटल इंडिया मशिन के तहत ई-प्रासीक्यूशन पोर्टल पर सूचनाएँ दर्ज कराने के मामले में भी सबसे आगे है।